राजस्थान समसामयिकी अप्रैल, 2025

संजीव वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी अप्रैल, 2025
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 April, 2025

राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीन नई नीतियाँ–लॉजिस्टिक नीति, डेटा सेंटर नीति और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति जारी की –

31 मार्च, 2025 को प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीन नई पॉलिसी विधिवत रूप से जारी की। इसमें लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति शामिल हैं। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में कार्यक्रम में सीएम ने इनकी घोषणा की। इन पॉलिसी के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-रूपांतरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टॉम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही अन्य शुल्क में 50 प्रतिशत तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा।

1. राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी : पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव–

- औद्योगिकी क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह एकत्रित हो और सुरक्षित हाथों में रहे। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों या उनके आस-पास डेटा सेंटर बनाए जाएंगे।
- दस वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव।
- सौ करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा।
- निवेश 5 साल के भीतर करना होगा।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सात साल तक 100 फीसदी छूट, बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन चार्ज में 10 साल तक सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। भू-उपयोग परिवर्तन का शुल्क भी नहीं लेंगे।
- ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) होगा।

2. लॉजिस्टिक पॉलिसी : मिलेगी औद्योगिक छूट–

- वेयरहाउस, साइलो, कोल्डस्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी, ईएफसीआई में 25 प्रतिशत छूट।
- निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी 7 प्रतिशत, स्टाम्प ड्यूटी, भू-रूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट होगी।
- प्रोजेक्ट लागत की 50 प्रतिशत राशि का एकमुश्त पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) तक हरित प्रोत्साहन मिलेगा।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

3. राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी : 12.5 करोड़ रुपए तक पुनर्भरण–

- दस वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव।
- भूमि-भवन खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। भू-रूपांतरण शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण होगा।
- ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) होगा।
- मेगा एवं अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं में स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण।
- राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फ्रेट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण।
- 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। 40 हजार करोड़ का निवेश संभावित।

राजस्थान वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा; 11-12 दिसम्बर, 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव होगा–

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निवेश उत्सव के अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने हर साल चैत्र शुक्ल

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस बार राजस्थान दिवस पर सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर महिला, किसान, युवाओं के उत्थान और गरीब कल्याण की कई सौगातें दी गईं।

मुख्यमंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ किया–

- 31 मार्च, 2025 को निवेश उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केन्द्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है।
- राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई, जो इन एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि निवेश का हर प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित हो सके।
- सतत् पर्यवेक्षण का ही परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान बनेगा–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में 'विकसित राजस्थान 2047' का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे।

16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी एमओयू पर भी डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लागू होगी–मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उन सभी एमओयू धारकों को शामिल किया गया, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार के साथ 15 मार्च तक एमओयू निष्पादित किए। निवेशकों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी नये एमओयू पर भी लागू किए जाने की घोषणा की।

18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी–

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा प्रदेश मैन्यूफैक्चरिंग का पावरहाउस बन सके।
- साथ ही, यहाँ सौर एवं पवन ऊर्जा की प्रचुरता ने भी पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है।
- इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला और दोहा में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राजस्थान निवेशकों के लिए स्वर्ग

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी और आर्थिक संभावनाओं से परिपूर्ण है, जो इसे निवेशकों के लिए स्वर्ग बनाता है।
- राजस्थान भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। पचपदरा (बालोतरा) में रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के प्रमुख हब के रूप में उभरेगा।
- हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन में भी अग्रणी है। राजस्थान बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्य के रूप में उभरा है। यहाँ देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
- मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लैव 2025 के लोगो का अनावरण किया तथा कॉन्क्लेव की आधिकारिक घोषणा की।

Newspaper of 2 April, 2025

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ('मा' योजना) में 9 रोगों के 132 नए पैकेज शामिल किए गए; रोबोटिक सर्जरी और आयुर्वेदिक इलाज भी नि:शुल्क होगा–

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 'मा (MAA)' में सरकार ने पहली बार आयुर्वेदिक सेवाओं व रोबोटिक सर्जरी के साथ नौ बीमारियों के 132 नए पैकेज और शामिल कर मरीजों को राहत दी है। एलोपैथिक इलाज नहीं लेने वाले रोगियों के लिए पहली बार आयुर्वेदिक में भी नि:शुल्क इलाज का रास्ता खोला है, इसमें 20 पैकेज शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं अति आधुनिक सेवाओं से भरपूर सरकारी स्तर पर रोबोटिक सर्जरी के 39 पैकेज को इस योजना में जोड़ा गया है। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में है। ये सभी पैकेज सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क होंगे। रोबोटिक सर्जरी के जरिए प्रोस्टेट कैंसर, मूत्राशय कैंसर, कैंसर ट्यूमर, कोलोरेक्टल सर्जरी, बेरिएट्रिक सर्जरी, हर्निया, एक्लेजिया कार्डिया समेत अन्य बीमारियों की सर्जरी की जा सकती है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

ये नए पैकेज शामिल हुए 'मा' योजना में–

- **5 पैकेज :** वृद्धावस्था देखभाल या जेरिएट्रिक केयर
- **2 पैकेज :** किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य
- **14 पैकेज :** ओरेल कैंसर (होठ, जीभ, मुँह के अंदरुनी हिस्से)
- **15 पैकेज :** दिव्यांग लोगों के लिए
- **20 पैकेज :** आयुर्वेदिक सेवाओं के
- **39 पैकेज :** रोबोटिक सर्जरी
- **7 पैकेज :** न्यूरो सर्जरी
- **3 पैकेज :** प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट सर्जरी।
- **27 पैकेज :** कार्डिक वस्कूलर सर्जरी।

रोबोटिक सर्जरी के फायदे–

- मरीज के शरीर के किसी भी जटिल हिस्से में आसानी से सर्जरी की जा सकती है।
- मरीज को दर्द और ब्लीडिंग नहीं होती।
- सर्जरी में समय कम लगता है।
- सर्जरी की सफलता दर ज्यादा होती है।
- मरीज को जल्द छुट्टी मिल जाती है।

■ **बालोतरा स्थित सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज के 1 लाख 11 हजार 845 टन के भंडारों की पुष्टि हुई; भारत की आयत पर निर्भरता कम होगी–**

हाल में राज्य के नए जिले बालोतरा स्थित सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। यहाँ करीब 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ खनिज मौजूद है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएँ और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा का सिवाना इलाका शामिल है। चीन की मॉनोपोली तोड़ने वाले इन खनिजों पर अब अन्वेषण से आगे तक परमाणु ऊर्जा विभाग कार्य कर रहा है। बाड़मेर जिले के सिवाना में रेअर अर्थ का बड़ा खजाना होने के संकेत एक दशक पहले ही मिले थे। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2021-22 से इस पर कार्य प्रारंभ किया। इसमें जी-4 (प्रारंभिक अन्वेषण) और जी-3 (संसाधन जुटाने के आगामी स्तर) तक कार्य चल रहा है।

बालोतरा में यहाँ चल रहा अन्वेषण : सेंजी की बेरी मेली, इंद्राणा सिवाना, सुकलेश्वर मंदिर, निमाड़े की पहाड़ी दंताला, कुंडल-धीरा, मवड़ी, सिलोर दंताला, कालूड़ी, टापरा, गुड़ानाल, बाछड़ाऊ (धोरीमन्ना), गूंगरोट, रेलों की ढाणी तेलवाड़ा सहित अन्य इलाकों में हैं।

जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेन्द्रसिंह ने कोयला मंत्री से संसद में जानकारी चाही। इस पर कोयला एवं खानमंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब में बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा जिले के कुछ हिस्से में कठोर चट्टानी इलाके में 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड (आरईओ) की खोज की है। राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत इस पर कार्य किया जा रहा है। सामरिक और महत्त्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर अभी राज्य में 35 परियोजनाएँ और 195 अन्वेषण का कार्य चल रहा है।

अभी यहाँ से कर रहे आयात : चीन की दुर्लभ धातु पर मॉनोपोली है। भारत प्रतिवर्ष चीन से 700 टन के करीब आयात कर रहा है। इसके अलावा हांगकांग, जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन, सिंगापुर, मंगोलिया से कम मात्रा में आयात कर रहा है। भारत का कुल आयात 1185 टन है।

Newspaper of 3 April, 2025

■ **वित्तीय वर्ष 2024-25 में खान विभाग ने सर्वाधिक राजस्व संग्रहण का नया कीर्तिमान बनाया; 23.35 प्रतिशत विकास दर के साथ 9,202 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहण–**

राजस्थान के खान विभाग ने वर्ष 2024-25 में 9202 करोड़ 50 लाख रुपये का राजस्व अर्जित कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है।

आरंभिक आंकड़ों के अनुसार खान विभाग ने 23.35% की विकास दर के साथ गत वित्तीय वर्ष से 1,742 करोड़ 2 लाख रुपये अधिक राजस्व संगृहीत किया है।

- खान विभाग के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष का अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रहण है।
- व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ ही सरलीकरण किया गया है।
- गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में खान विभाग द्वारा 7460 करोड़ 48 लाख रुपये का राजस्व संगृहीत किया गया था।
- मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान देश में पहले पायदान पर आ गया है, अब राजस्व विकास दर में भी संभवत: राजस्थान देश में पहले स्थान पर आ गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में इसी वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रधान और अप्रधान खनिज ब्लॉकों तथा प्लाटों की नीलामी, नई खनिज नीति, नई एम-सेंड नीति के साथ ही राइजिंग राजस्थान के दौरान खनिज क्षेत्र में निवेश करार हुए हैं।

Newspaper of 4 April, 2025

■ **फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में नंबर वन, केन्द्र से 562 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा; प्रदेश में अब तक 73.17 लाख 826 रजिस्ट्री हुई, डीडवाना प्रथम स्थान पर–**

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

केन्द्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में राजस्थान देशभर में पहले स्थान पर है। कुल 81.13 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अब केन्द्र सरकार राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में 562 करोड़ का इंसेंटिव देगी।

राजस्थान ने इसके लिए क्लेम भी पेश कर दिया है। 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते ही राजस्थान 394 करोड़ का दावा भी पेश करेगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान को 90 लाख 19 हजार 695 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य दिया था। राज्य में अब तक 73 लाख 17 हजार 826 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है।

इसके लिए 17 फरवरी से 31 मार्च तक राज्य में प्रत्येक तहसील की 3-5 ग्राम पंचायतों में 600 फार्मर रजिस्ट्री कैंप प्रतिदिन लगाए गए। फार्मर रजिस्ट्री करने में मध्यप्रदेश दूसरे, आंध्रप्रदेश तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और गुजरात पाँचवें स्थान पर है।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री–फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट का यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जाएगा। इसके लिए भू-अभिलेख के डेटाबेस को समेकित कर राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम वाले किसान व समान पिता के नाम वाले किसानों के ऑनलाइन बकेट (समस्त जानकारी एक साथ) तैयार कर मोबाइल एप, वेबसाइट द्वारा राज्य के सभी खसरों को शामिल करते हुए किसान के आधार से लिंक किया जाएगा। इसके बाद किसान से ऑनलाइन सहमति लेते हुए एक एनरोलमेंट आईडी बन जाएगी। इससे 24 घंटे में किसान की फार्मर आईडी जेनरेट होगी।

Newspaper of 5 April, 2025

■ **राजस्थान सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 'राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना' की अधिसूचना जारी की; अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष–**

- 4 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 'राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना' (आरजेएचएस) की अधिसूचना जारी की गई।
- इस योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा में 28 मार्च को राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था।
- राज्य सरकार से अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार आरजेएचएस के लिए पात्र होंगे। इस योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद अधिस्वीकृत पत्रकारों को आरजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- योजना के अनुसार, पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की चिकित्सा व्यय (आईपीडी) की सुविधा मिलेगी।
- साथ ही, ओपीडी की सुविधा मेडिकल डायरी के अनुसार देय होगी।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को योजना के तहत मिलने वाली सुविधा के लिए आईडी कार्ड भी जारी किए जाएंगे।
- योजना में बीमित व्यक्ति को आरजीएचएस में परिभाषित अनुमोदित अस्पतालों में किए गए सभी इनडोर उपचारों तथा शल्य चिकित्साओं के लिए कैशलेश सुविधा प्रदान की जाएगी।
- अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तथा पंद्रह दिन बाद तक की अवधि के दौरान किए गए प्रासंगिक चिकित्सा व्यय को दावे के हिस्से के रूप में माना जाएगा।
- आरजेएचएस योजना के तहत मातृत्व चिकित्सा, अन्तः रोगी उपचार (आईपीडी) और अन्य चिकित्सा सुविधाएँ कैशलेस उपलब्ध होंगी।

■ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अब जिला कलक्टर के स्तर से भी सूची में नाम जुड़ और हट सकेंगे–**

- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं।
- इसी क्रम में जिला कलक्टर को भी एनएफएसए में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है।
- जिला कलक्टर को भी एनएफएस में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करने से पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी हो सकेगी। इस निर्णय से पात्रों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी।

Newspaper of 6 April, 2025

■ **जयपुर डेयरी ने 23 नए वैरिएंट और समिति सदस्यों की बेटियों के लिए मायरा योजना लॉन्च की–**

5 अप्रैल, 2025 को जयपुर डेयरी के 50 साल पूरे होने पर बिरला ऑडिटोरियम में गोल्डन जुबली समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डेयरी ने 23 नए वैरिएंट और समिति सदस्यों की बेटी के लिए मायरा योजना लॉन्च की। नए वैरिएंट में 3 कोल्ड कॉफी, 5 फ्लेवर्ड मिल्क और 10 कैंडी आइसक्रीम और श्रीखंड के 5 नए फ्लेवर्स शामिल हैं। सरस की आईसक्रीम की न्यूनतम कीमत 5 रुपए रखी है। मायरा योजना के तहत जयपुर डेयरी में दूध देने वाले सदस्यों की बेटियों की शादी में 21000 रुपए नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए डेयरी

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

रूफटॉप सोलर प्लांट योजना और बायो-फ्लेक्सी प्लांट स्कीम शुरू की गई। सोलर प्लांट योजना के तहत जयपुर डेयरी जयपुर और दौसा जिले की 3400 समितियों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। वहीं जैविक कचरे से घर पर मुफ्त रसोई गैस बनाने के लिए शुरू की गई बायोफ्लेक्सी प्लांट स्कीम में समितियों को ₹ 5000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस प्लांट के जरिए हर महीने 1.5 सिलेंडर गैस का उत्पादन किया जा सकेगा।

Newspaper of 7 April, 2025

- **राजस्थान प्रदेश को जीरे की नई किस्म 'जोधपुर जीरा-1' के नाम से पहचान मिली–**

राजस्थान के किसानों को 22 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश को जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी 'जोधपुर जीरा-1' मिल गई है। केन्द्रीय किस्म विमोचन समिति (सीएससी) ने इस वैरायटी को दिल्ली में हुई बैठक में आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले 2004 में गुजरात की किस्म जीसी-4 जारी की गई थी।

इस नई किस्म को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सात वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। इसका नेतृत्व विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रमेश चौधरी ने किया। यह वैरायटी न केवल अधिक उपज देती है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बेहतरीन है। 'जोधपुर जीरा-1' का परीक्षण राजस्थान और गुजरात के 5 प्रमुख कृषि केन्द्रों पर किया गया, जहाँ यह किस्म उपज, पौधा विकास और शाखा संख्या में उत्कृष्ट साबित हुई। वर्तमान में किस्म को सीएससी से मंजूरी मिल चुकी है तथा राज्य कृषि विभाग इसके बीज उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। आगामी सीजन में किसान इस नई किस्म को अपने खेतों में बो सकेंगे। वर्ष 2024 में भारत ने करीब 5000 करोड़ रुपए का जीरा निर्यात किया था। जोधपुर जीरा-1 की नई किस्म से पुरानी किस्म जीसी-4 की तुलना में 22.7% ज्यादा होगा उत्पादन। इससे उकठा और कालिया जैसे रोगों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

Newspaper of 9 April, 2025

- **9 अप्रैल, 2025 को ब्रह्माकुमारीज की प्रमुख 101 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का देवलोकगमन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के जाइडिस अस्पताल में रात्रि 1.30 बजे अंतिम सांस ली। उल्लेखनीय है कि दादी रतन मोहिनी मात्र 13 वर्ष की आयु में ही ब्रह्माकुमारीज संस्थान से जुड़ी और पूरा जीवन समाज कल्याण में समर्पित कर दिया।**

- **जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण सीतापुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 किमी. का होगा; ₹ 10000 करोड़ खर्च होंगे व 35 स्टेशन बनेंगे–**

जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण 36 किमी का होगा। सीतापुरा से सीकर रोड (टोड़ी मोड) तक जाएगी। एयरपोर्ट के आसपास मेट्रो ट्रेन भूमिगत रहेगी और करीब 32 किमी का सफर एलिवेटेड होगा। इस प्रोजेक्ट पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार को राइट्स ने ड्राफ्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसका आंतरिक परीक्षण चल रहा है। मेट्रो अधिकारियों की माने तो परीक्षण के दौरान कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। दरअसल, राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के बाद फेज-2 को धरातल पर लाने का काम शुरू हुआ है।

खास-खास–

प्रत्येक किमी में एक स्टेशन का दिया गया है प्रस्ताव।

34 स्टेशन एलिवेटेड और एयरपोर्ट पर प्रस्तावित स्टेशन होगा भूमिगत।

ये रहेगा रूट–

सीतापुरा से पिंजरापोल गौशाला तक एलिवेटेड रूट होगा। इसके बाद गौशाला से आगे मेट्रो का कॉरिडोर भूमिगत होगा।

सीतापुरा–सांगानेर पुलिस स्टेशन के पास टोंक रोड पर ही भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। इस स्टेशन से यात्री सांगानेर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक तक जा सकेंगे। इसके बाद फिर एलिवेटेड रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। बी-टू-बाइपास चौराहे से अशोक मार्ग तक (टोंक रोड़) रूट एलिवेटेड होगा। अशोक मार्ग से गवर्नमेंट हॉस्टल, खासाकोठी सर्कल से कलेक्ट्रेट सर्कल, चिंकारा कैंटीन, पानीपेच अंबाबाड़ी तक रूट प्रस्तावित है। सीकर रोड़ पर भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान से हरमाड़ा और उससे आगे टोड़ी मोड़ तक मेट्रो जाएगी। सीकर रोड पर बने बीआरटीएस कॉरिडोर का उपयोग मेट्रो के लिए किया जाएगा।

Newspaper of 11 April, 2025

- **रामदेवरा से पोकरण तक नई रेल लाइन को मंजूरी मिली–**

हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामदेवरा से पोकरण तक नई रेल लाइन को मंजूरी देने की घोषणा की है। यह लाइन कैलाश टेकरी और भैरव गुफा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए गुजरेगी। इससे न केवल आस्था के स्थलों तक पहुँच आसान होगी, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी नया बल मिलेगा। यह नया ट्रेक सीधे पोकरण से जुड़ाव प्रदान करेगा, जिससे बीकानेर व जोधपुर से जैसलमेर आने वाली

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

ट्रेनों की गति में सुधार हो सकेगा और करीब 45 मिनट का समय बचेगा। इंजन और डिब्बों की अदला-बदली में लगने वाला समय की भी बचत हो सकेगी।

Newspaper of 12 April, 2025

■ जयपुर के रामगढ़ बाँध का पुनः जीर्णोद्धार होगा; ईसरदा बाँध से पानी लाकर पुनः भरा जाएगा।

11 अप्रैल, 2025 को जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने रामगढ़ बाँध के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास किया। यहाँ पर पानी लाने से पहले बाँध की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसके बाद राम जल सेतु लिंक योजना से पानी लाया जाएगा। सरकार ने 1945 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शिलान्यास किया।

ये कार्य होंगे–

- रामगढ़ बाँध की पाल पर बनी 2 किमी. क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत की जाएगी।
- पाल पर पैराबेट वॉल का निर्माण कार्य किया जाना है।
- ऐतिहासिक गुम्बद छतरी की मरम्मत और सौन्दर्यीकरण किया जाएगा।
- कन्ट्रोल रूप के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
- पाल पर पत्थर का कार्य किया जाएगा।

राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा, इनको मिलेगा फायदा–रामगढ़ बाँध को राम जल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ा गया है। ईसरदा बाँध से रामगढ़ बाँध तक पानी लाने का अलाइनमेंट तय हो चुका है। निविदा जारी हो गई है। दोनों बाँधों के बीच की दूरी करीब 120 किमी है। इसमें 35 किमी नहर और 85 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पानी आने पर लाखों से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलेगा। सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। वर्तमान में जमवारामगढ़ का ज्यादातर क्षेत्रफल ड्राई जोन में ही है। रामगढ़ बाँध को ईआरसीपी के प्रथम चरण में शामिल करने से बाँध के जलभराव क्षेत्र में रोड़ा नदी, ताला नदी व बहुत से बरसाती नालों के आसपास बसे सैकड़ों गाँवों सहित लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पशु-पक्षियों, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा।

Newspaper of 13 April, 2025

■ राज्य सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप (अतिमहत्त्वपूर्ण) कार्यक्रम घोषित किया; पूर्व सरकार की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया–

राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन सहित 25 योजनाओं को फ्लैगशिप (अतिमहत्त्वपूर्ण) कार्यक्रम घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय केन्द्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं की सीधे मॉनिटरिंग करेगा। संबंधित विभाग को हर महीने की सात तारीख तक इनमें हुए कार्य और खर्च की जानकारी सीएमओ भेजनी होगी। इनमें पूर्व सरकार की 26 फ्लैगशिप योजनाओं में से किसी को शामिल नहीं किया गया है।

आयोजना विभाग ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित करने का आदेश जारी किया। इसके अनुसार जिलों के प्रभारी मंत्री, सचिव इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे।

सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में हरियाळो-राजस्थान, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, पंच गौरव योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाना तथा नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी व पशु सखी योजना को शामिल किया है। कुसुम योजना, बिजली में संशोधित वितरण योजना, लाडो योजना, कृषि सिंचाई योजना को भी जगह दी गई है।

आयुष्मान सहित अन्य योजनाएँ शामिल–

इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केन्द्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण व पीएम विश्वकर्मा योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाया है।

Newspaper of 14 April, 2025

■ बारां जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ–

11 अप्रैल, 2025 को प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बारां जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

सिर्फ तीन रुपये में बर्तन सेट मिलेगा–

इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों से मात्र तीन रुपये किराए पर शादी एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बर्तन सेट प्राप्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण में बारां जिले की 24 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। भविष्य में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

सरकार एक लाख रुपये की राशि देगी–
राज्य सरकार ने योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना से न केवल प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी, बल्कि गांवों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी मजबूती मिलेगी।

ये बर्तन सेट में शामिल होंगे–राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सेट में तीन कटोरी, एक थाली, एक गिलास और एक चम्मच शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 400 सेट रखे जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और 'स्वच्छ भारत मिशन' अंकित किया जाएगा। बर्तन पाँच वर्षों के बाद बदले जा सकेंगे, हालांकि अच्छी स्थिति में रहने वाले बर्तन आगे भी उपयोग में लिए जा सकेंगे।

विशेष वर्गों को रियायत मिलेगी–बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तनों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। बर्तनों की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा, जबकि जबकि संचालन राजीविका के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई बर्तन टूटता या खो जाता है, तो उपयोगकर्त्ता से उसकी भरपाई की जाएगी।

Newspaper of 16 April, 2025

■ **रावतभाटा स्थित परमाणु बिजलीघर की 7वीं इकाई (क्षमता 700 MW) से बिजली बनने लगी; 320 मेगावाट पर उत्पादन शुरू कर नेशनल ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति शुरू की–**

15 अप्रैल, 2025 को स्वदेशी राजस्थान परमाणु बिजलीघर को 7वीं इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। 700 मेगावाट क्षमता की इस इकाई को 50% क्षमता पर चलाने की आण्विक ऊर्जा नियामक बोर्ड की मंजूरी है। इस पर पहले दिन 320 मेगावाट पर उत्पादन शुरू कर नेशनल ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति कर दी गई है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर पर स्वदेशी रूप से विकसित पहली 700 मेगावाट की 7वीं इकाई के सभी अनिवार्य परीक्षणों को पूर्ण कर लिया गया है।

लगभग 23 हजार करोड़ की राजस्थान परमाणु बिजलीघर की 7वीं-8वीं इकाई परियोजना पिछले 14 साल से चल रही है। 14 साल के बाद अब लगभग 8 करोड़ रुपए एक इकाई से प्रतिदिन की कमाई शुरू हो गई है।

देश की 25वीं परमाणु बिजलीघर इकाई–7वीं इकाई देश की 25वीं इकाई है। 24 परमाणु बिजलीघरों से कुल 8080 मेगावाट का उत्पादन देश में हो रहा है। अब उत्पादन क्षमता 8780 मेगावाट हो गई है। जबकि रावतभाटा में पहले से 1080 मेगावाट उत्पादन हो रहा था। अब उत्पादन क्षमता 1780 मेगावाट हो गई है। 8वीं इकाई के बाद रावतभाटा में उत्पादन क्षमता 2480 मेगावाट हो जाएगी।

8वीं इकाई से विद्युत उत्पादन की तैयारी–7वीं इकाई में विद्युत उत्पादन शुरू होने के बाद अब 8वीं इकाई में कमिशनिंग की प्रक्रिया में तेजी कर दी गई है। स्थल निदेशक शरतकुमार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाए।

यह है स्वदेशी इकाई की विशेषता–राजस्थान परमाणु बिजलीघर की 700 मेगावाट की इकाई में 2 कूलिंग टावर हैं, जबकि 220 मेगावाट में एक कूलिंग टावर होता है। यह इकाई पूरी तरह से भूकंपरोधी है। साथ ही मिसाइल हमले से इसका डोम सुरक्षा प्रदन करता है। यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और नियमों की आधुनिकता के साथ में इसका निर्माण किया गया है। इसमें पहली बार में 1 लाख 15 हजार 248 किलो यूरेनियम फ्यूल भरा गया है। यह इकाई ऐसी है, जिसके लिए यूरेनियम फ्यूल का बंडल के रूप में निर्माण भी यहीं हो रहा है। मंदक और शीतलक के लिए भारी पानी का निर्माण भी यहीं से होकर आपूर्ति हो रही है।

Newspaper of 17 April, 2025

■ **राजस्थान विधानसभा में पारित चार नए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिली; तत्काल प्रभाव से लागू हुए–**

हाल ही में राज्य विधानसभा के बीते सत्र में पारित चार विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। 16 अप्रैल, 2025 को इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके साथ ही यह चारों कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है। इसमें प्रमुख रूप से आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान से जुड़ा विधेयक भी शामिल है, जिसे राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट सत्र में रख दिया था। लेकिन पास दूसरे बजट सत्र में हो सका। इसी तरह प्रदेश के 33 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर अब कुलगुरु हो गया है।

1. **राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024–**
   यह कानून आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़े एवं ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मीसा या जेल में निरूद्ध किए गए राजस्थान मूल के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिए जाने से संबंधित है। वर्तमान में 1140 लोकतंत्र सेनानी या उनके आश्रित हैं, जिन्हें 20 हजार रुपए मासिक पेंशन, चार हजार रुपए चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह और रोडवेज बसों में नि:शुल्क

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

यात्रा का प्रावधान है। इनकी मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन काल के लिए यह सब सुविधाएँ देय होंगी। राष्ट्रीय उत्सवों में इन्हें आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल पहले नियम बनाकर इन्हें यह सुविधाएँ दी जा रहीं थीं, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था। भाजपा सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया है।

2. **राजस्थान विधियाँ निरसन अधिनियम-2025**–राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस कानून के तहत राजस्थान में 45 अप्रचलित एवं पुराने कानून समाप्त कर दिए हैं। निरसित किए गए अधिकांश कानून पंचायतीराज विभाग से जुड़े हुए थे। जिनका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं रह गया था। विधानसभा में यह बिल पारित करते समय सरकार ने दावा किया था कि इन कानूनों के निरस्त किए जाने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनया जा सकेगा। क्योंकि, ये कानून अनावश्यक जटिलताएँ पैदा कर रहे थे।
3. **राजस्थान विधियाँ संशोधन अधिनियम-2025**– राजस्थान नगर सुधार न्यासों एवं प्राधिकरणों में अब न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। राज्यपाल ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण और न्यासों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता को समाप्त करने वाले बिल को मंजूदी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय के बाद ही यह बिल लाया गया था। इससे किसी भी प्राधिकरण की शक्तियाँ समाप्त नहीं होंगी। राज्य सरकार सभी न्यासों एवं प्राधिकरणों के लिए एक समान सेवा शर्तों का निधारण कर सकेगी।
4. **राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियाँ संशोधन विधेयक-2025**–33 विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम अब कुलगुरु और प्रतिकुलपति का प्रतिकुलगुरु हो गया है। हालांकि अंग्रेजी में कुलपति वाइस चांसलर ही कहलाएंगे। नाम बदलने के पीछे सरकार का दावा था कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य गुरु करता है। विश्वविद्यालयों में कुलपति मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होता है। जहाँ कुलपति शब्द प्रशासनिक एवं स्वामित्व को दर्शाता है।

Newspaper of 18 April, 2025

■ केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 975 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का पोकरण क्षेत्र के भिणाजपुरा गाँव में लोकार्पण किया; यह 100 प्रतिशत मेक इन इंडिया; 90 प्रतिशत मेक इन राजस्थान; बिजली 2.18 रुपए यूनिट की दर से राजस्थान को ही मिलेगी–

17 अप्रैल, 2025 को पोकरण क्षेत्र के भिणाजपुरा गाँव से रिन्यू कंपनी के 975 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट है, जो पूरी तरह 'मेक इन इंडिया' है। इसमें लगे 100 प्रतिशत उपकरण (सोलर मॉड्यूल), सामान देश में बने हैं और इसमें भी 90 प्रतिशत हिस्सा जयपुर स्थित सेज की मेन्युफेक्चरिंग यूनिट में निर्मित किया है।

मात्र 15 माह में तैयार हुआ प्लांट–पोकरण और भनियाना तहसील के कई गांवों में करीब 3500 एकड़ में प्लांट फैला है। रिन्यू कंपनी के सीईओ सुमंत सिन्हा ने कहा कि प्लांट केवल 15 माह में तैयार कर चालू कर दिया गया है। कंपनी प्रदेश के डिस्कॉम्स को 2.18 प्रति यूनिट की दर पर सप्लाई करेगी। इसके लिए अनुबंध हो चुका है। इससे सलाना करीब 2490 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे प्रदेश के 5 लाख उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। यहाँ उत्पादित बिजली से राजस्थान में ही आपूर्ति की जाएगी।

■ राजस्थान सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी की–

हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, 2024 जारी कर दी है। नीति में नए हवाई अड्डों के विकास की प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएँ देने के लिए कहा गया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओएस) सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात कही गई है।

नीति के अनुसार राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हैलीपेड, सरकारी और निजी विमानों व हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति जिला कलक्टर दे सकेंगे। अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायुसेवा प्रदाताओं, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की हवाई पट्टियों और हैलीपेड के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अग्निशमन वाहनों एंबुलेंस और नए हैलीपेड निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए है, राजस्थान में एफटीओएस की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर एवं प्रक्रिया भी तय की गई है।

राज्य की स्थिति–

- 10 एयरपोर्ट व 23 हवाई पट्टियाँ
- 4 एयरपोर्ट (जयपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन
- 6 एयरपोर्ट (बीकोनर, बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ एवं फलौदी) वायुसेना के पास

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- 19 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के स्वामित्व में
- 4 हवाई पट्टियाँ निजी के पास

Newspaper of 19 April, 2025

गुजरात को पीछे छोड़कर राजस्थान फिर अक्षय ऊर्जा में अव्वल; राजस्थान की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 34,136 मेगावाट हुई–

गुजरात को पीछे छोड़कर राजस्थान 34136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। गुजरात में स्थापित ऊर्जा क्षमता 33393 मेगावाट है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।

अभी की स्थिति–वर्तमान में देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2,20,096.35 मेगावाट है।

राज्य	अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता
♦ राजस्थान	34,136
♦ गुजरात	33,393
♦ तमिलनाडु	25,241
♦ कर्नाटक	23,917
♦ महाराष्ट्र	22,401
♦ हिमाचल प्रदेश	12,196
♦ आंध्रप्रदेश	12,114
♦ मध्यप्रदेश	10,827

राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की–

हाल ही में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

- बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
- योजना के तहत आवेदक छात्र/छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।
- ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णत: पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अभ्यर्थी की स्वयं की वार्षिक आय को सम्मलित करते हुए अधिकतम 5 लाख रुपये से कम हो, उनके दो बच्चे पात्र होंगे।
- राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से लिये गये केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत शुल्क का पुनर्भरण/भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम की एक से अधिक वर्ष की अवधि होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा।
- आवेदनकर्त्ता को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय पर करना होगा।

Newspaper of 26 April, 2025

राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम अब अहिल्याबाई होल्कर भवन किया गया–

हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा योजनाओं के नाम बदले हैं। कुछ योजनाएँ बंद भी कर दी गईं। शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम भी बदल दिया है। अब यह भवन पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होल्कर भवन के नाम से जाना जाएगा। इस भवन में विद्यार्थी सेवा केन्द्र, विद्या समीक्षा केन्द्र और केन्द्रीय मूल्यांकन का कार्य होता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का कार्यालय भी इसी भवन में है। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का संचालन भी यहीं से हो रहा है।

1 मई, 2025 से एकमुश्त समाधान योजना-2025 का प्रथम चरण शुरू होगा, ओटीएसएस के तहत ऋणियों को राहत मिलेगी–

राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएम-एफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) लागू की है।

- प्रथम चरण 1 मई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा।
- इस चरण में 31 मार्च, 2024 को ऋणियों के बकाया अतिदेय (ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर, 2025 तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दण्डनीय ब्याज) में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
- द्वितीच चरण एक अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगा।
- इस चरण में 31 मार्च, 2024 को ऋणियों के बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा कराने पर ऋणी की शास्ति (दण्डनीय ब्याज) में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 27 April, 2025

■ राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान अव्वल रहा–

इस वर्ष 8 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्रीज से पीछे छूट गया है।

पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों द्वारा इस बार 1,18,60,962 गतिविधियों की एंट्रीज की गई। जबकि दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों द्वारा 1,09,51,961 गतिविधियों की एंट्रीज की गई है। तीसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र के 36 जिलों द्वारा 67,12,236 गतिविधियों की एंट्रीज की गई है।

इन जिलों ने लक्ष्य से कई गुना अधिक प्रदर्शन किया– राजस्थान के 33 जिलों में से कई ने तो लक्ष्य से कई गुना अधिक प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश में जन भागीदारी और विभागीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इनमें 25 अप्रैल 2025 तक की गतिविधियों के अनुसार चूरू 15,36,980 एंट्रीज कर प्रथम, श्रीगंगानगर 16,73,684 एंट्रीज कर द्वितीय, हनुमानगढ़ 9,21,718 एंट्रीज कर तृतीय, टोंक 9,09,097 एंट्रीज कर चतुर्थ और बीकानेर 8,90,367 एंट्रीज कर पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया।

प्रभाव और परिणाम– लाभार्थियों में पोषण के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। गर्भवती, धात्री महिलाएँ और किशोरियों में उचित आहार व्यवहार अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। पोषण ट्रेकर में रजिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा के माध्यम से निगरानी प्रणाली मजबूत हुई। समुदायों में स्थानीय पोषण ज्ञान और संस्कृति का आदान-प्रदान किया गया।

Newspaper of 28 April, 2025

■ राजस्थान में पहली बार बाघिन ने पाँच शावकों को जन्म दिया; 4 गोल्डन एवं 1 व्हाइट शावक–

हाल ही में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। खास यह है कि प्रदेश में पहली बार एक साथ 5 शावक जन्में हैं और इसके साथ ही एक बाघिन द्वारा लगातार दूसरी बार व्हाइट टाइगर को जन्म दिया गया है। इसके साथ ही पार्क में व्हाइट टाइगर की संख्या दो हो गई है। उल्लेखनीय है कि बाघिन रानी ने 10 महीने 18 दिन पहले 10 मई, 2024 को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें दो की मौत हो गई थी, नर वाइट टाइगर भीम और मादा स्कन्धी अभी सकुशल हैं।

Newspaper of 30 April, 2025

■ कृष्ण गमन पथ के राजस्थान रूट में 8 मंदिर शामिल होंगे; राजस्थान धरोहर प्राधिकरण और विशेषज्ञों की कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय; पथ का निर्माण यूपी, एमपी और राजस्थान सरकार मिलकर करेंगी–

भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा में कंस का वध करने के बाद अध्ययन के लिए उज्जैन की यात्रा की थी। भागवत महापुराण के अनुसार, देवकी पुत्र कृष्ण ने महर्षि सांदीपणि से शस्त्र, शास्त्र और आध्यात्मिक विद्याएँ प्राप्त की थीं। बड़े भाई हलधर बलराम के साथ वे उज्जैन में महर्षि सांदीपणि के गुरुकुल में रहे। भगवान कृष्ण के इस महत्त्वपूर्ण मार्ग की धार्मिक यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं को देने के लिए सरकार 'कृष्ण गमन पथ' के निर्माण की योजना बना रही है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित विशेषज्ञों की कमेटी ने पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिथिगृह में हुई बैठक में कृष्ण गमन पथ के राजस्थान रूट पर चर्चा की। मथुरा से उज्जैन तक धार्मिक यात्रा के इस नए मार्ग में राजस्थान के आठ मंदिर शामिल किए गए हैं। इनमें भरतपुर का श्रीबिहारीजी मंदिर, बयाना के झील का बाड़ा का कैलादेवी, कैमरी (करौली) का जगन्नाथ मंदिर, करौली का मदनमोहनजी मंदिर, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर, बूँदी का केशवरायजी महाराज मंदिर, कोटा के मथुराधीश और झालरापाटन (झालावाड़) के द्वारकाधीश मंदिर शामिल हैं।

□□□

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

50 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

मनोहर सिंह कोटड़ा के मार्गदर्शन में तैयार पुस्तकें

(41 जिलों एवं 7 संभागों पर आधारित नवीनतम संस्करण)

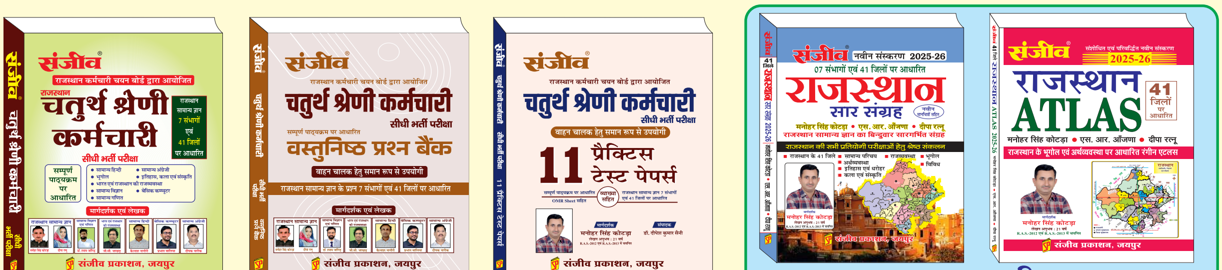

शीघ्र उपलब्ध

कैलाश नागौरी की संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

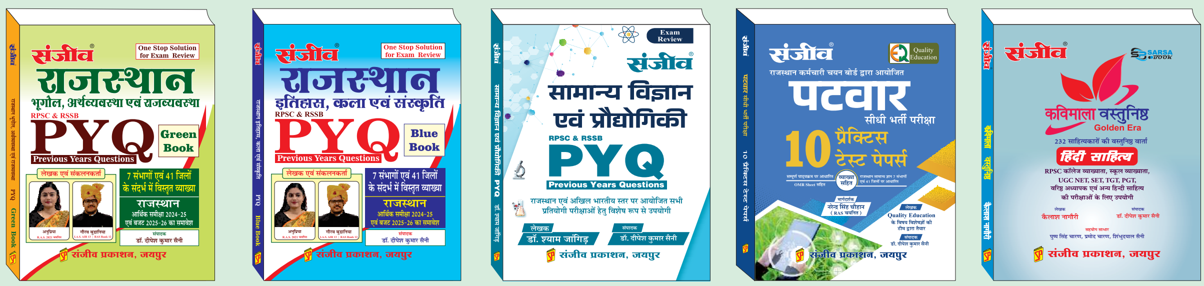

संजीव प्रकाशन

Join Our Telegram

संजीव Telegram चैनल एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com